

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-100/2012

सांवरमल

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 09.07.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थागण विभाग की ओर से : श्री राजेश निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दे रहा है। प्रकरण पुराना है। अतः अपील का निस्तारण पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पंचायत समिति, फागी, जिला जयपुर की स्थाई समिति की बैठक के पश्चात आदेश दिनांक 03.08.1999 (अनुलग्नक-2) से हुई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 41 पर है। उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूरा होने पर स्थाई किया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की तिथि 09.07.1986 दर्शायी गई और दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 09.07.1988 दर्शाई गई। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 09.07.1988 को स्थाई घोषित किया गया था। यह भी तथ्य अंकित किये गये हैं कि जिला परिषद जयपुर ने आदेश दिनांक 06.11.2000 जारी कर दिनांक 01.01.1986 से दिनांक 31.12.1987 तक नियुक्त एवं निरंतर कार्यरत अध्यापक जो योग्यता रखते हैं, को नियमित करते हुए वरिष्ठता का लाभ दिया गया। इसके संबंध में आदेश दिनांक 25.09.2009 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 234 पर दर्शाया गया है एवं वरिष्ठता क्रमांक 317 दर्शाया गया है। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये

हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 09.07.1986 मानते हुए उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 09.07.1995 से आदेश दिनांक 30.12.1995 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी ने 18 वर्ष की सेवा दिनांक 09.07.2004 को पूर्ण कर ली थी। अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 09.07.2004 से दिया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने निर्धारित प्रपत्र विभाग को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने आगे यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अति. जिला शिक्षा अधिकारी फागी जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2012 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि अपीलार्थी का द्वितीय चयनित वेतनमान के लिये जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर कार्यालय में भेजा गया था। वहां पर लेखाधिकार ने नोट लाकर वापिस भिजवा दिया एवं उसे द्वितीय चयनित वेतनमान 06.11.2018 के पश्चात प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:—

“(i) यह कि विवादित आदेश दिनांक 24.01.2012 व प्रदर्श-7 खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को यह निर्देश दिया जावे कि वह अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि 09.07.1986 मानते हुए उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 09.07.2004 से देवे।

(ii) यह कि अप्रार्थीगण को यह भी निर्देश देवे कि उसे द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ की बकाया राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान करें।

(iii) अन्य कोई लाभ जो माननीय अधिकरण उचित समझता है उसे अपीलार्थी के हक में पारित करें।”

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी अध्यापक को नियमानुसार कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर के आदेश क्रमांक संनि/स्कूलशिक्षा/मा/जय/संस्था-5/फा-एसीपी लेवल/102/2020 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी का परिलाभ दिनांक 06.11.2018 से स्वीकृत किया जा चुका है, उक्त आदेश दिनांक 05.03.2020 में कम० सं० 17 पर अपीलार्थी के नाम के सम्मुख अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 06.11.2000 अंकित की गई है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.03.2020 को अपीलार्थी द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है तथा अपीलार्थी को नियमानुसार पेंशन परिलाभ भी स्वीकृत किया जा चुका है। निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/स्थिरी/2702/98 दिनांक 22.12.1998 के द्वारा राज्य सरकार से यह मार्गदर्शन चाहा गया था कि पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा विभाग में स्थानांतरित होकर आये कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण स्क्रीनिंग के बाद इनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही कर दिये जाने के फलस्वरूप क्या इन कर्मचारियों की सेवायें भूतलक्षी प्रभाव से नियमित मानी जा सकती है। इस संबंध में विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.18 (4) शिक्षा-5/98 दिनांक 06.02.1999 से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 4(11)पी. एण्ड जे/आरडी./पी/87 192 दिनांक 17.03.1989 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी किये जाने की तिथि से ही नियमित मानी जावेगी। उक्त आदेशों के अनुसरण में ही अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 06.11.2000 मानी गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 06.11.2018 से देय है जो कि प्रदान किया जा चुका

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा किये गये अभिकथनों पर विचार किया गया।
5. अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति नहीं थी, वह अस्थाई नियुक्ति थी। बाद में स्क्रीनिंग करने के पश्चात अपीलार्थी को शिक्षा विभाग ने नियमित किया। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य रखे गये हैं कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति के 2 वर्ष पूर्ण करने पर स्थाई किया गया था, जिसका आदेश पंचायत समिति द्वारा पारित किया गया था। ऐसे में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवा की गणना की जायेगी। अपीलार्थी ने यह प्रकट नहीं किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई हो, बल्कि अपीलार्थी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई थी एवं अपीलार्थी का 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर पंचायत समिति द्वारा अपीलार्थी को स्थाई किये जाने से यह नहीं माना जा सकता की अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नियमानुसार स्थाई पद हेतु की गई हो। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ही नियमानुसार होना प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि अस्थाई नियुक्ति होना प्रकट हुआ है।
6. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

7. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रिनिंग के पश्चात ही नियमित की गयी है। उससे पूर्व की सेवा तदर्थ रूप में दी गयी थी। नियमितिकरण की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवाएं नियमित मानी जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं स्क्रिनिंग के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)